बोकारों इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

735. **श्री गया सिंह**: क्या इस्पात तथा ख़ान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारों इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के दूसरे चरण को आरम्भ करने से संबंध में सरकार के निर्णय का पूर्ण विवरण क्या हैं?

इस्पात तथा ख़ान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं।

National action Plan for steel sector

736. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a national action plan for steel sector;

(b) if so, the main objectives and the details of the action plan;

(c) whether any proposal to invite multinational investment is under consideraiton of Government in order to modernise the steel industry; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) to (d) Based on reports of the Working Groups set up for vairous sectors of the economy, the Planning Commission prepares a National Plan for five years. The Working Group on Iron and Steel for the IXth Five Year plan set up by the Planning Commission has projected a likely domestic demand of 38.68 million tonnes of Finished Carbon Steel by 2001-02 including an export potential of 6 million Tonnes. The main objective of the plan is to ensure that the demand for steel in the country is met indigenously. As per the projections made by the Working Group, the produciton of Finished Carbon Steel will reach 38.012 Million Tonnes by 2001-02 against the projected demand of 38.68 Million Tonnes. The increase in production of steel is expected to come from modernisation and expansion of existing Integrated Steel plants and creation of new capacities in the private sector. The Working Group has also projected a total investment of about Rs. 52,498 crores in the steel sector during IX Five Year Plan with public sector investing around Rs. 20,005 crores. Keeping in tune with the present economic policy, Deptt. of Steel is endeavouring to facilitate creation of new capacities by making realistic projections of demand, removal of bottlenecks through inter action with the entrepreneurs, financial institutions and State Governments etc.

निजी इस्पात संयंत्रों से प्राप्त वार्षिक आय

373. **श्री गोपाल सिंह जी.सांलकी**: क्या इस्पात तथा ख़ान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान सरकार को निजी इस्पात संयंत्रों से कितनी वार्षिक आय हुई;

(ख) सरकार ने इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने हेतु वर्ष 1998-99 में निजी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की हैं;

(ग) देश के इस्पात उत्पादन में निजी संयत्रों का प्रतिशत कितना हैं ;

(घ) क्या निजी उत्पादक देश में इस्पात की खपत को पूरा करने में सक्षम हैं;और

(ड़) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

इस्पात और ख़ान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैंस): (क) इस्पात विभाग इस सूचना का प्रबोधन नहीं करता।

(ख) नई औद्योगिक नीति के अनुसार कतिपय स्थान संबंधी प्रतिबंधों के अलावा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए 1998-99 के दौरान कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया हैं।